

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1888
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के तहत आवंटित धनराशि

1888. श्री विद्युत बरन महतोः

श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री दिलीप शश्कीयाः
श्री पी.सी. मोहनः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री भोजराज नागः
श्री विजय बघेलः
श्री करण भूषण सिंहः
श्री नव चरण मांझीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जून 2025 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिलावार ब्यौरे सहित राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक ओडिशा सहित देश में इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या राज्यवार कितनी है।
- (ग) इन परियोजनाओं में से छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा क्षेत्र सहित देश में कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और परिणामस्वरूप उनकी प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता में कितनी वृद्धि है;
- (घ) जालौर और सिरोही जिलों सहित राजस्थान में डेयरी संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवंटित कुल धनराशि और प्रदान की गई राजसहायता की कुल राशि कितनी है;
- (ङ) क्या उक्त योजना से विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा क्षेत्र में मत्स्यपालन और डेयरी उत्पादों की बर्बादी में कमी आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) पीएमकेएसवाई से मध्य प्रदेश, विशेष रूप से देवास-शाजापुर लोक सभा क्षेत्र के विकास में किस प्रकार सहायता मिली है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) केंद्रीय क्षेत्र की एक मांग आधारित योजना है और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत जून, वर्ष 2025 तक देश में अनुमोदित कुल धनराशि का हिमाचल प्रदेश के जिलावार ब्यौरा सहित राज्यवार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में दिया गया है।

(ख) और (ग): जनवरी, वर्ष 2024 से जून, वर्ष 2025 तक ओडिशा सहित देश भर में 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनका राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है। इनमें से एक परियोजना चालू हो गई है। ब्यौरा **अनुबंध-4** में दिया गया है।

(घ): जालौर और सिरोही जिलों सहित राजस्थान में डेयरी संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए स्वीकृत और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा अनुबंध **-5** में दिया गया है।

(ङ): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा वर्ष 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत शीत शूखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव" पर किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, यह रेखांकित किया गया था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत शूखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के हस्तक्षेप के कारण, जहाँ सभी क्षेत्रों में अपव्यय में आंशिक कमी देखी गई, वहाँ फल और सब्जियां, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अपव्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई। दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा **अनुबंध-6** पर दिया गया है।

(च): पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2025 तक, मध्य प्रदेश राज्य में 52 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 30 परियोजनाएँ कुल परियोजना लागत 642.57 करोड़ रुपये के साथ पूर्ण/कार्यरत हैं। जिससे 9442 रोजगार के अवसर संजित हुए हैं और 87341 किसान लाभान्वित हुए हैं। देवास - शाजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-7** पर दिया गया है।

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि" के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत देश में जून, वर्ष 2025 तक राज्यवार स्वीकृत कुल धनराशि				
क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत जीआईए (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार	2	5.36	3.17
2	आंध्र प्रदेश	77	3293.90	762.11
3	अरुणाचल प्रदेश	12	177.89	82.51
4	असम	106	1224.11	435.35
5	बिहार	15	748.76	170.60
6	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10	284.31	89.47
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	26.34	3.64
9	दिल्ली	21	31.15	10.90
10	गोवा	2	31.33	7.71
11	गुजरात	107	2634.63	653.99
12	हरियाणा	98	1502.18	400.26
13	हिमाचल प्रदेश	44	730.05	298.47
14	जम्मू और कश्मीर	40	386.92	194.32
15	झारखण्ड	2	3.10	0.94
16	कर्नाटक	95	1341.77	394.75
17	केरल	51	985.37	303.86
18	लद्दाख	0	0.00	0.00
19	लक्ष्मीप	0	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	52	1021.26	355.66
21	महाराष्ट्र	245	4764.52	1305.04
22	मणिपुर	8	117.29	59.19
23	मेघालय	10	117.08	71.92
24	मिजोरम	4	107.01	66.32
25	नागालैंड	6	131.34	78.90
26	उड़ीसा	28	748.72	206.85
27	पुडुचेरी	2	0.81	0.81
28	पंजाब	76	1566.31	427.07
29	राजस्थान	55	1049.02	305.37
30	सिक्किम	1	6.17	3.64
31	तमिलनाडु	145	1924.52	497.70
32	तेलंगाना	67	1631.34	394.44
33	त्रिपुरा	9	118.89	66.24
34	उत्तर प्रदेश	97	1953.17	476.24
35	उत्तराखण्ड	59	1057.54	476.05
36	पश्चिम बंगाल	54	934.44	249.90
	कुल	1601	30656.57	8853.38

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि" के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- 2

जून, वर्ष 2025 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जिलावार स्वीकृत कुल धनराशि

जिले का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ में)
बिलासपुर	4	19.69	8.62
कांगड़ा	4	10.5672	6.65
कुल्लू	2	42.78	12.45
शिमला	8	220.75	65
सिरमौर	2	19.7147	11.43
सोलन	14	197.6009	96.91
ऊना	10	218.9538	97.39
कुल योग	44	730.0566	298.45

“दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु “पीएमकेएसवार्इ के अंतर्गत आवंटित निधि” के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक ओडिशा सहित देश में स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	1
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	3
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	2
कर्नाटक	1
केरल	3
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	10
ओडिशा	2
पंजाब	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	7
तेलंगाना	4
उत्तर प्रदेश	1
उत्तराखण्ड	1
पश्चिम बंगाल	3
कुल योग	52

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु “पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि” के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक देश में स्वीकृत 52 परियोजनाओं में से चालू परियोजनाओं का विवरण

योजनाएं	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ज़िला	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति	रोज़गार	लाभान्वित किसान	प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता एलएमटी/वर्ष
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना	तेलंगाना	विमता लैब्स लिमिटेड	प्राइवेट	हैदराबाद	दिनांक 01-03-2024	10.82	4.09	4.0949	प्रचालनरत	37	शून्य	शून्य

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु “पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि” के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान में डेयरी से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों के लिए स्वीकृत और जारी की गई कुल धनराशि			
ज़िला	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
बाड़मेर	1	7.26	2.42
बीकानेर	1	3.01	3.01
हनुमानगढ़	1	3.34	3.34
जयपुर	4	22.24	22.24
कोटा	1	6.59	6.59
कुल योग	8	42.44	37.60

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु “पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि” के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग ((ड)) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का व्यौरा											
क्र.सं.	योजनाएं	राज्य	परियोजना का नाम	ज़िला	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति	रोजगार	लाभान्वित किसान
1	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना (एपीसी)	छत्तीसगढ़	मेसर्स के के एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	बेमेतरा	दिनांक 28.02.2024	68.866	10	0	कार्यान्वनाधीन	2273	4000

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु “पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि” के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 1888 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- 7

देवास - शाजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का व्यौरा

क्र.सं.	योजनाएं	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ज़िला	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति	रोज़गार	लाभान्वित किसान
1	मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी)	मध्य प्रदेश	अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड		देवास	दिनांक 31-12-2015	146.07	50.00	40.00	प्रचालनरत	240	6000
2	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)	मध्य प्रदेश	मेसर्स ऑयस्टर एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेन मिलिंग	देवास	दिनांक 08.07.2023	20.50	4.53	2.2665	कार्यान्वनाधीन	52	1000

3	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सूजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)	मध्य प्रदेश	मेसर्स पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	दूध प्रसंस्करण	शाजापुर	09.08.2023	19.05	3.80	1.7	कार्यान्वनाधीन	153	1000
---	---	-------------	---	----------------	---------	------------	-------	------	-----	----------------	-----	------